

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 18826/2018

रंजन टाक पुत्र श्री राम प्रताप टाक, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने, राजमहल, गुलाबसागर, जोधपुर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ जरिए सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री
2. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिए निदेशक (एच. आर.), भर्ती खंड: पिन-110070।
3. प्रभारी, कॉर्पोरेट भर्ती तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तेज भवन, देहरादून,

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए:

श्री सुनील पुरोहित

उत्तरदाता(गण) के लिए:

डॉ. सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री करण परिहार, श्री ओ. पी. मेहता वी. सी. द्वारा।

न्यायाधिपति दिनेश मेहता**निर्णय****रिपोर्ट करने योग्य 02/09/2023**

1. याचिकाकर्ता ने इस अदालत से इस व्यथा के साथ संपर्क किया है कि प्रतिवादी ने उसकी दृष्टि बाधा के कारण उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया है।
2. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सामग्री प्रबंधन अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया है, जो प्रतिवादी-तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए विज्ञापन दिनांक 3/18 (R& P) (अनुलग्नक-1) के अनुसार है।
3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त विज्ञापन द्वारा कुल 49 सीटों को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से 19 सीटें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित थीं और एक सीट हार्ड ऑफ हियरिंग व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, विषय विज्ञापन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यह पद ओ. ए.,

ओ. एल., बी. एल., एच. एच. और एल. वी. श्रेणी (एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर, सुनने में कठिनाई और कम दृष्टि) श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।

4. याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन पत्र ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में जमा किया और पी. एच. श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नहीं, हालांकि वह 30 प्रतिशत दृष्टिबाधित था।

5. याचिकाकर्ता को मेधावी पाया गया और उसे 25.09.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से नियुक्ति की पेशकश की गई, बशर्ते कि प्रतिवादी-निगम के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। जब याचिकाकर्ता की चिकित्सा जांच की गई, तो बोर्ड ने कहा कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता की बाईं आंख में 30 प्रतिशत तक की हानि होने के कारण उसकी दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य नहीं है और इसलिए वह अयोग्य है।

6. जब याचिकाकर्ता को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्होंने प्रत्यर्थी-निगम के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि वह 'पीएच' श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण का दावा किए बिना मेधावी थे और उन्हें (30 प्रतिशत विकलांग) नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब अधिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाता है और नियुक्ति की पेशकश की जाती है।

7. पुनरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को दिनांक 27.11.2018 के आक्षेपित संचार के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। विवादित संचार का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: -

"3. ओ. एन. जी. सी. के चिकित्सा मानदंडों के अनुसार, उम्मीदवार के पास अच्छी उभय दृष्टि होनी चाहिए। नियमित नियुक्ति के लिए एक नेत्र वाले व्यक्ति को अयोग्य माना जाना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि ओ. एन. जी. सी. एम. ई. आर.-1 प्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आई/सी-मेडिकल सर्विसेज द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के अनुसार आपके पास उभय दृष्टि नहीं है। ओ. एन. जी. सी., मुंबई,

आपको चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि आप उपरोक्त शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता की बाईं आंख में 30 प्रतिशत की हानि है, कहा कि उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित करने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई आत्यन्तिक रूप अवैध और मनमाना है।
9. उन्होंने तर्क दिया कि जब सामग्री प्रबंधन अधिकारी के पद को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है और कम से कम 19 पदों को निर्धारित किया गया है और आगे यह तथ्य कि इस तरह के पद को नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले (बी. एल. और एल. वी.) व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है, तो कम विकलांग (30 प्रतिशत) याचिकाकर्ता को पद के लिए अयोग्य घोषित करना अनुचित है।
10. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के साथ केवल कम हानि होने या बेंचमार्क विकलांगता की तुलना में कम विकलांग होने के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिससे वह 'पीएच' श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण का दावा करने का हकदार हो जाता। यह तर्क दिया गया कि यह देखना बेतुका था कि प्रतिवादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त मान रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता को उसकी आंख में 30 प्रतिशत हानि होने के कारण अयोग्य मान रहे हैं।
11. विद्वान वकील ने जोर देकर तर्क दिया कि जब तक याचिकाकर्ता एक अंधे व्यक्ति या कम दृष्टि वाले व्यक्ति के रूप में आरक्षण का दावा नहीं करता है, तब तक उसकी आंख में विकलांगता का प्रतिशत नियुक्ति प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकता है, विशेष रूप से जब समान हानि वाले व्यक्तियों को उपयुक्त माना जाता है।
12. अदालत ने अदालत में मौजूद याचिकाकर्ता के साथ बातचीत की। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह एक इंजीनियर है जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से बी. टेक की डिग्री प्राप्त की है। यह पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि उनकी आंख में हानि जन्म के समय नहीं हुई थी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वे क्रिकेट खेल रहे थे, एक गेंद उनकी बाईं आंख में लगी और गेंद के स्ट्रोक ने उनकी बाईं आंख में विकृति पैदा कर दी।

लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि जिस होनहार लड़के ने प्रत्यर्थी-निगम द्वारा आयोजित भर्ती में 81.48% अंक प्राप्त किए हैं और योग्यता में 10वें स्थान पर ^{रहा} है, उसने इसे अभिशाप के रूप में नहीं लिया और आईआईटी (रुड़की) में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम है।

13. विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील पुरोहित ने वर्षा नरवानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस. बी. सिविल रिट **याचिका No.13034/2018**) के मामले में दिए गए समन्वय पीठ के दिनांक **14.05.2019** के आदेश और रेखा मीना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। (एस. बी. सिविल रिट **याचिका No.1325/2020**) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक **27.02.2020** का निर्णय पर भरोसा किया।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता विज्ञापन की स्थिति से अवगत था, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि जिन व्यक्तियों की उभय दृष्टि अच्छी है, उन्हें ही स्वस्थ माना जाएगा। यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को विज्ञापन की शर्त को चुनौती देनी चाहिए थी यदि वह भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने से पहले इतना व्यथित था।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी के पास दृष्टिबाधित लोगों के लिए सीमित सीटें (19) उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को केवल उन निर्धारित पदों पर तैनात किया जा सकता है और दृष्टि में कठिनाई वाले अधिक व्यक्तियों को प्रतिवादी के संगठन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुन गया।

17. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को अपनी दृष्टि में 30 प्रतिशत चुनौती मिल रही है। इस न्यायालय के विचार के लिए जो विवादास्पद प्रश्न सामने आया है, वह यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो मेधावी होने के बावजूद 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक)' के तहत आरक्षण के लिए निर्धारित मापदंड से कम दुर्बलता रखता है, वह चिकित्सा आधार पर गैर-उपयुक्त हो सकता है, विशेष रूप से जब पद समान विकलांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया हो।

18. इस प्रश्न का उत्तर, इस न्यायालय की राय में, निश्चित रूप से 'नहीं' है।
19. इस न्यायालय के अनुसार, जब केंद्र सरकार या प्रतिवादी ने उचित विवेक के बाद विशेष प्रकार के विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उपयुक्त किसी विशेष पद की पहचान की है और आगे यदि 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षमता वाले उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया गया है, तो उस विशेष प्रकार की अक्षमता वाले अन्य उम्मीदवारों को शेष या अनारक्षित सीट पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य मानना अतार्किक और मनमाना है।
20. इस न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति जो कम विकलांग है, उसे कम चोट या हानि देने के लिए प्रकृति को कोसते रहने के लिए मुश्किल में नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रतिवादी के प्रतिगामी दृष्टिकोण के कारण, याचिकाकर्ता लगातार पश्चाताप करेगा और सोचेगा-'काश! मैं अधिक अक्षम होता। '
21. प्रतिवादी का रुख-निगम कि केवल 19 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं और उत्तरदाता इससे अधिक व्यक्तियों को समायोजित नहीं कर सकते हैं, एक ओर तथ्यात्मक रूप से गलत है और दूसरी ओर अतार्किक है।
22. परिणाम (Annex.4) के अवलोकन से पता चलता है कि केवल 11 विकलांग व्यक्तियों (VH) को नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि VH श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों की संख्या 19 थी।इसलिए, निगम का यह कहना कि वे अधिक उम्मीदवारों को समायोजित नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार्य है, क्योंकि वी. एच. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पदों (8) की संख्या अभी भी खाली है।
23. यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता, एक मेधावी उम्मीदवार जिसने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की कट-ऑफ से भी बहुत अधिक अंक (81.48) प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित/PH श्रेणी का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है और यह कि याचिकाकर्ता जिसने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद सभी व्यावहारिक सहित अपनी B.Tech डिग्री पूरी कर ली है और उसके बाद G.A.T.E पास कर लिया है। (इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट) उसे सौंपे गए सभी कर्तव्यों/जिम्मेदारियों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर सकता है, इस अदालत को लगता है कि यदि उसे किसी भी कार्यात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो याचिकाकर्ता को उन कर्तव्यों का पालन करने के

लिए कहा जा सकता है जो वीएच व्यक्तियों के लिए आरक्षित 19 पदों के लिए कथित रूप से निर्धारित किए गए हैं।

24. कानूनी स्थिति पर चलते हुए, यह एक ज्ञात तथ्य है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए, संसद ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद '2016 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को अधिनियमित किया और केंद्र सरकार ने 2016 के अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 (इसके बाद '2017 के नियम' के रूप में संदर्भित) बनाए।

25. 2016 के अधिनियम और 2017 के नियमों के नियम 3 के प्रावधान, जो वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"2. परिभाषाएँ/- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(ग) "बाधा" से संचार, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत, राजनीतिक, सामाजिक, दृष्टिकोण या संरचनात्मक कारकों सहित कोई भी कारक अभिप्रेत है जो समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है;

(ज) अक्षमता के संबंध में "भेदभाव" का अर्थ है अक्षमता के आधार पर कोई भेद, बहिष्कार, प्रतिबंध जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की दूसरों के साथ समान आधार पर मान्यता, आनंद या अभ्यास को बाधित करने या रद्द करने का उद्देश्य या प्रभाव है और इसमें सभी प्रकार के भेदभाव और उचित समायोजन से इनकार शामिल है।

(आर) "मानक अक्षमता वाला व्यक्ति" का अर्थ है एक निर्दिष्ट अक्षमता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाला व्यक्ति जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें एक विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है;

(ओं) "विकलांग व्यक्ति" से दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जो बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है;

3. समानता और गैर-भेदभाव।

(1) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि.....

(2).....

(3) किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विवादित कार्य या चूक एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।

20. रोजगार में गैर-भेदभाव -

(1) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा:

33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान- उपयुक्त सरकार -

(i) उन प्रतिष्ठानों में पदों की पहचान करें जो खंड 34 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की संबंधित श्रेणी द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं;

(ii) ऐसे पदों की पहचान के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना; और

(iii) चिन्हित पदों की तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर आवधिक समीक्षा करना।

नियम 3. अक्षमता के आधार पर भेदभाव न करने के लिए प्रतिष्ठान।

(1) प्रतिष्ठान का प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की खंड 3 की उप-खंड (3) के प्रावधान का दुरुपयोग अधिनियम के तहत आने वाले विकलांग व्यक्तियों को किसी भी अधिकार या लाभ से वंचित करने के लिए नहीं किया जाता है।

(2) यदि बीस या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले सरकारी प्रतिष्ठान या निजी प्रतिष्ठान के प्रमुख को किसी पीड़ित व्यक्ति से

विकलांगता के आधार पर भेदभाव के बारे में शिकायत मिलती है, तो वह -

- (ए) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू करें; या
- (ख) पीड़ित व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करें कि कैसे विवादित कार्य या चूक एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।
- (3) यदि पीड़ित व्यक्ति, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त को शिकायत प्रस्तुत करता है, तो शिकायत का निपटान साठ दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा:
बशर्ते कि असाधारण मामलों में, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त तीस दिनों के भीतर ऐसी शिकायत का निपटारा कर सकते हैं।
- (4) कोई भी प्रतिष्ठान किसी विकलांग व्यक्ति को उचित आवास के लिए किए गए खर्च का आंशिक या पूरी तरह से भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

26. धारा 2 (एच) और 3 (3) के उपरोक्त प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम के प्रमुख भाग (ओं) को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि 2016 का अधिनियम प्रत्यर्थी-निगम (जो पूरी तरह से उपयुक्त सरकार की परिभाषा के भीतर आता है) पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव न किया जाए।

27. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2016 के अधिनियम और 2017 के नियमों द्वारा दो समान प्रतीत होने वाले, लेकिन कानूनी रूप से अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया गया है-"बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति", जिन्हें 2016 के अधिनियम की खंड 2 के खंड (आर) और (ओं) में विधिवत परिभाषित किया गया है। निर्दिष्ट अक्षमता वाला व्यक्ति जिसकी अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, उसे मानक अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जाता है।

28. 2016 के अधिनियम का अध्याय II बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जिनमें से खंड 32,33 और 34 अभिन्न अंग हैं। 2016 के अधिनियम की खंड 32 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करती है, जबकि खंड 33 और 34 पदों की पहचान और ऐसे पदों के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण निर्धारित करती है।

29. यह ध्यान रखना उचित है कि अधिनियम की खंड 3 विशेष रूप से, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है-यह सभी विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे उनकी अक्षमता की प्रकृति और सीमा कुछ भी हो। यदि उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए, तो 2016 के अधिनियम की खंड 3 की उप-खंड (3) स्पष्ट रूप से यह ध्यान दें देती है कि किसी विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि आक्षेपित कार्य या चूक एक वैध लक्ष्य प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।

30. इस न्यायालय के अनुसार, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (इसके बाद 'निर्देश' के रूप में संदर्भित) में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के संबंध में सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण को दिए गए निर्देशों के खंड V (आंखें) के साथ संलग्न नोट संख्या (iii) स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है और कम से कम वर्तमान तथ्यों में 2016 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

31. आपत्तिजनक शर्त अन्य पदों के लिए मान्य हो सकती है, लेकिन 'सामग्री प्रबंधन अधिकारी' के संबंध में, जब पद की पहचान कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए की गई है और 19 पद दृष्टिबाधित (वीएच) व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो विवादित शर्त को स्वीकार करना होगा। चूंकि सामग्री प्रबंधन अधिकारी के पद के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति की श्रेणी की पहचान की गई है, इसलिए उभय दृष्टि होने की स्थिति अपने आप में एक विरोधाभास है।

32. इस न्यायालय की राय में, नेत्रों, कानों, श्रवण दोषों और चाल या गति आदि के लिए निर्धारित मानदंडों या मानदंडों को शारीरिक चुनौती से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा जांच करते समय तदनुसार समझा या शिथिल किया जाना चाहिए, यदि ऐसी चुनौती या विकलांगता को स्वीकार्य माना गया है, बल्कि संबंधित पद के लिए उपयुक्त माना गया है। इसे अलग तरह से व्यक्त करने और इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, यह माना जाता है कि "यदि किसी पद को किसी विशेष प्रकार की विकलांगता के लिए उपयुक्त माना गया है और यदि कोई व्यक्ति ऐसी विकलांगता से पीड़ित है, तो उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि उसने आरक्षण का दावा नहीं किया है या उसकी विकलांगता उसे आरक्षण का दावा करने का हकदार बनाने के लिए निर्धारित मानदंड से कम है।

33. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो परिणाम अन्यायपूर्ण और असमान होगा।

34. वर्तमान मामले में बेंचमार्क विकलांगता वाले 11 व्यक्तियों का चयन किया गया है (जिन्हें 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता थी) इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उनकी उभय दृष्टि सामान्य नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता को उभय दृष्टि नहीं होने या 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उत्तरदाताओं की कार्रवाई भेदभावपूर्ण होने के अलावा, सभी तर्कों की अवहेलना करती है और वही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार की अवहेलना करती है।

35. प्रतिवादी की ऐसी कार्रवाई/कार्य 2016 के अधिनियम की खंड 3 की उप-खंड (3) के तहत भी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का विस्तार इतना व्यापक माना गया है कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

36. याचिकाकर्ता, वर्तमान मामले में, एक याचिका के साथ आया है कि वह अपनी श्रेणी (ओ. बी. सी.-नॉन क्रीमी लैअर) में अपनी योग्यता के आधार पर विचार किए जाने का हकदार है, न कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के आधार पर।

37. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 2016 के अधिनियम और 2017 के नियमों को न केवल समान अवसर प्रदान करने के लिए, बल्कि शारीरिक या मानसिक चुनौतियों से पीड़ित व्यक्ति की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी लागू किया गया है। अधिनियम और नियमों के प्रावधान लाभकारी और सुधारात्मक प्रकृति के हैं और इसलिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रावधानों और प्रासंगिक शर्तों को सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें अधिनियमित किया गया था। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के घोषित उद्देश्य के आलोक में, प्रतिवादी की विवादित कार्रवाई पूरी तरह से अस्थिर और मानवाधिकारों और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार के खिलाफ प्रतीत होती है।

38. उन्होंने कहा, "क्रिकेट खेलते समय याचिकाकर्ता की आंख में लगी एक गेंद से काफी चोट लगी है। प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को उसके वैध अधिकार से वंचित करके और उसे सबसे बुरा सोचने के लिए मजबूर करके ऐसी चोट के लिए नमक रगड़ने की

अनुमति नहीं दी जा सकती है, कि गेंद से 10 प्रतिशत अधिक चोट लगनी चाहिए थी, ताकि उसकी योग्यता को रौंदा न जा सके और उसे कम से कम आरक्षित सीटों के खिलाफ नियुक्ति मिल सके। हमारी जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था और जीवंत समाज में और उज्ज्वल युवाओं के एक विकासशील देश में, इस तरह का आंख बंद करने वाला दृष्टिकोण तर्कसंगतता की कसौटी को पार नहीं कर पाता है। समाज के मनोबल को बढ़ाने और देश के सामाजिक आर्थिक वातावरण को ऊपर उठाने के लिए इस तरह के दृष्टिकोण की बाधा, जो एक अन्यथा मेधावी उम्मीदवार के भविष्य को बाधित करती है, को दूर किया जाना चाहिए।

39. इस न्यायालय के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की दुर्दशा के प्रति राज्य और उसके साधनों को संवेदनशील बनाना भी है।

40. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में कहा गया है कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि कम विकलांग व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उसी धारा में और समान विकलांगता वाले व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य माना जाएगा।

41. ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है; दिनांकित 27.11.2018 (Annex.9) के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

42. प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सामग्री प्रबंधन अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता को उस पद के खिलाफ नियुक्ति दें, जिसे इस मामले में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.12.2018 के अनुसार खाली रखने का आदेश दिया गया है।

43. याचिकाकर्ता 05.10.2018 से नोशनल लाभों का हकदार होगा, जिस तारीख को उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था।

44. स्थगन याचिका का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(दिनेश मेहता), जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।